+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(07 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **RBI** की नवीनतम मौद्रिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे
- संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित
- बीजू जनता दल द्वारा 'पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना' का विरोध क्यों हो रहा है?
- **MCQ**

RBI की नवीनतम मौद्रिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे:

नवीनतम मौद्रिक नीति के प्रमुख निष्कर्ष:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 दिसंबर को वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के प्रयास में नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों (bps) की कटौती कर इसे 4.5% से घटाकर 4% कर दिया।
- हालांकि, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 4-2 के बहुमत के फैसले में रेपो दर – प्रमुख नीति दर – को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। 22 महीनों में यह लगातार ग्यारहवीं मौद्रिक नीति है, जिसमें रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि MPC ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया।
- साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को 'तटस्थ' बनाए रखने का भी फैसला किया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) क्या होता है?

- नकद आरक्षित अनुपात (CRR) रिज़र्व बैंक की एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमाराशि का एक निश्चित प्रतिशत रिज़र्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना होता है।
- अब तक यह बैंक की शुद्ध मांग और समय देयताओं (NDTL) का 4.5 प्रतिशत निर्धारित था, इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपये की जमा राशि के लिए बैंकों को RBI के पास 4.50 रुपये रखने होंगे। अब इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

CRR की उपयोगिता:

- उल्लेखनीय है कि CRR के प्राथमिक उद्देश्यों में तरलता प्रबंधन शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि बैंक जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा कर सकें और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रख सकें।
- CRR को समायोजित करके, रिज़र्व बैंक उधार देने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को प्रभावित करता है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
- CRR में समय-समय पर समायोजन रिज़र्व बैंक को बदलती आर्थिक स्थितियों के प्रति गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, जिससे यह भारत में मौद्रिक नीति के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

CRR में कटौती क्यों की गई है?

- CRR में कटौती का यह निर्णय बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंगी और GDP वृद्धि में गिरावट के बीच लिया गया है, जो 2024 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.4 प्रतिशत तक धीमी हो गई - जो सात तिमाहियों का निचला स्तर है।
- रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि CRR में कटौती रिज़र्व बैंक की अपनी नीतिगत स्थिति को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता का संकेत है।
- उल्लेखनीय है कि CRR में 50 BPS की कटौती के फैसले से बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपये की नकदी बढ़ेगी, जो अब तक रिज़र्व बैंक के पास जमा थी और उस पर बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में इससे बैंकों के पास उधार देने के लिए संसाधन बढ़ेंगे।
- उल्लेखनीय है कि रुपये को स्थिर करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा बहुत अधिक डॉलर की बिक्री भी की गई है, जिससे सिस्टम में कुल लिक्विडिटी प्रभावित हुई है। दिसंबर में, GST के अग्रिम कर भुगतान से संबंधित निकासी और तिमाही के अंत में ऋण की मांग के कारण लिक्विडिटी और भी कम हो जाएगी।

- ऐसे में बैंकों द्वारा CRR के कटौती से मुक्त अधिशेष लिक्विडिटी का उपयोग ऋण देने के लिए किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बात की भी संभावना है कि बैंक इस CRR कटौती का लाभ उधारकर्ताओं को दे सकते हैं।

रेपो दर (RR) को अपरिवर्तित क्यों रखा गया है?

- प्रमुख नीतिगत दर, रेपो दर (RR) को अपरिवर्तित रखने के लिए MPC का 4-2 का निर्णय यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के मद्देनजर आगे के रास्ते के बारे में नीति समिति में मतभेद हैं।
- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बहुमत के फैसले के लिए अपने स्पष्टीकरण में लगातार खाद्य मुद्रास्फीति को चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि "वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बना रहने की संभावना है और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कम होना शुरू हो जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के हाथों में डिस्पोजेबल आय को कम करती है। ऐसे में MPC का मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ, हम उच्च विकास के लिए मजबूत आधार सुरक्षित करते हैं"।

- उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में, दो केंद्रीय मंत्रियों ने रेपो दर में कटौती का आह्वान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगों को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के लिए "सस्ती बैंक ब्याज दरों" की वकालत की। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने RBI से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मौद्रिक नीति पर निर्णय लेते समय खाद्य कीमतों पर विचार करने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का आग्रह किया।

MPC ने GDP विकास पूर्वानुमान क्यों घटाया है?

- MPC ने दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में कम वृद्धि दर के मद्देनजर GDP विकास पूर्वानुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि क्रमशः जून, अगस्त और अक्टूबर की MPC घोषणाओं में, RBI ने तिमाही वृद्धि में मामूली बदलाव के साथ 2024-25 के लिए GDP विकास अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा था।
- इस मामले में रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दूसरी तिमाही में कम वृद्धि दर अपने निचले स्तर पर पहुंच गई और उसके बाद से त्योहारी मांग और ग्रामीण खपत के कारण इसमें सुधार हुआ है।

- NSO द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जुलाई-सितंबर 2024 में सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4% पर आ गया है। जो अप्रैल-जून 2024 तिमाही में 6.7% था।

MPC ने मुद्रास्फीति पर क्या कहा - और क्यों?

- MPC ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति (CPI), या खुदरा मुद्रास्फीति, सितंबर में 5.5% की तुलना में अक्टूबर 2024 में 6.21% के 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- MPC ने लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति के मद्देनजर दरों में कटौती की सीमित गुंजाइश पर प्रकाश डालते हुए सतर्क रुख बनाए रखा है। क्योंकि मुद्रास्फीति का स्तर RBI के सहनीय स्तर से बहुत ऊपर बना हुआ है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित:

चर्चा में क्यों है?

- संसद ने 5 दिसंबर को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जिसने 90 साल पुराने 1934 के विमान अधिनियम की जगह ले ली।
- इस विधेयक को 9 अगस्त को लोकसभा में मंजूरी दी गई और राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया।
- इस महत्वपूर्ण विधायी कदम का उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना है।

भारतीय वायुयान विधायक 2024 के प्रमुख उदेश्य:

- इस विधेयक का उद्देश्य है:
  - ➢ पुराने विमान अधिनियम, 1934 को बदलना, जिसमें 21 बार संशोधन किया जा चुका है।
  - ➢ विमानन में सुरक्षा, विनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना।

➢ विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और निवेश को प्रोत्साहित करना।

➢ नागरिक विमानन प्राधिकरणों के लिए शासन संरचनाओं को मजबूत करना।

- नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक के शीर्षक का अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तन भारत की विरासत और संस्कृति को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप है।

हवाई यात्रा में सुगमता और वहनीयता को बढ़ाना:

- उड्डयन मंत्री ने 'उड़ान' योजना के तहत प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसके तहत आठ वर्षों में 86 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का संचालन करके और 609 मार्गों को शुरू करके सुगमता में सुधार किया गया है। साथ ही वहनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा:
- हवाई किराए की निगरानी: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइनें यात्रियों का शोषण न करें, टिकट की कीमतों की निगरानी करती है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वर्ष की तुलना में दिवाली के मौसम में प्रमुख क्षेत्र के टिकट की कीमतों में 2-42 प्रतिशत की कमी आई है।

- संशोधित परिपत्र: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के 2010 के परिपत्र में संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत एयरलाइनों को 24 घंटे के भीतर कीमतों में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइनों को अब एक महीने पहले किराया विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ईंधन मूल्य में कमी के प्रयास: दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा विमानन ईंधन पर लगाए गए उच्च वैट को एक चुनौती के रूप में चिह्नित किया गया। उड्डयन मंत्री ने सांसदों से परिचालन लागत कम करने के लिए वैट में कटौती की वकालत करने का आग्रह किया।

विधेयक का नाम बदलने के सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ:

- इस विधेयक का नाम बदलकर हिंदी करने पर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ सदस्यों ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए समर्थन दिया, जबकि अन्य ने इसे अनावश्यक बताते हुए इसका विरोध किया। भाजपा सांसद राम चंद्र जांगड़ा ने हिंदी को "देश का गौरव" बताया और सदस्यों से इस भाषा को अपनाने का आग्रह किया।

हवाई यात्रा और डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना:

- हाल के महीनों में बढ़ती धमकी कॉल के कारण सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
- 'डिजीयात्रा' की डेटा सुरक्षा पर, उड्डयन मंत्री ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि आधार जैसे व्यक्तिगत डेटा को उनके डिवाइस पर संग्रहीत किया जाता है और हवाई अड्डे के उपयोग के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है।

निवेश को प्रोत्साहित करना और एकाधिकार को कम करना:

- यह विधेयक विमानन में संभावित एकाधिकार पर चिंताओं को संबोधित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विपक्षी सांसदों ने एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा द्वैधता के मुद्दे उठाए, जिसके परिणामस्वरूप हवाई किराए में वृद्धि हुई। और कुछ सांसदों ने हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र में अदानी, टाटा और इंडिगो जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के कथित प्रभुत्व पर चिंता व्यक्त की।

भारतीय विमानन क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं:

- भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है। विनियामक ढांचे को

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

आधुनिक बनाकर और निवेश को बढ़ावा देकर, विधेयक का उद्देश्य विकास, पहुंच, सामर्थ्य और सुरक्षा को संतुलित करना है।

- जबकि सरकार उच्च हवाई किराए और बुनियादी ढांचे की बाधाओं जैसी चुनौतियों से निपट रही है, वह उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए भारत को एक अग्रणी वैश्विक विमानन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बीजू जनता दल द्वारा 'पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना' का विरोध क्यों हो रहा है?

चर्चा में क्यों है?

- नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल (बीजद) ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है। बीजद का आरोप है कि इस परियोजना से ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासियों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा।
- 4 दिसंबर को बीजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर परियोजना के बैकवाटर पर नए सिरे से अध्ययन की मांग की। अधिकारियों ने बीजद के इस कदम को एक "राजनीतिक स्टंट" बताया है, क्योंकि उनके अनुसार, परियोजना का 75% हिस्सा पहले ही विकसित हो चुका है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है?

- पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना गोदावरी नदी पर एक अंतरराज्यीय परियोजना है जिसकी परिकल्पना 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की सिफारिशों के एक भाग के रूप में की गई थी।
- 2 अप्रैल, 1980 को, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने 150 फीट के पूर्ण जलाशय स्तर और 36 लाख क्यूसेक की स्पिलवे डिस्चार्ज क्षमता वाली परियोजना के निर्माण को मंजूरी देने के लिए एक समझौता किया।

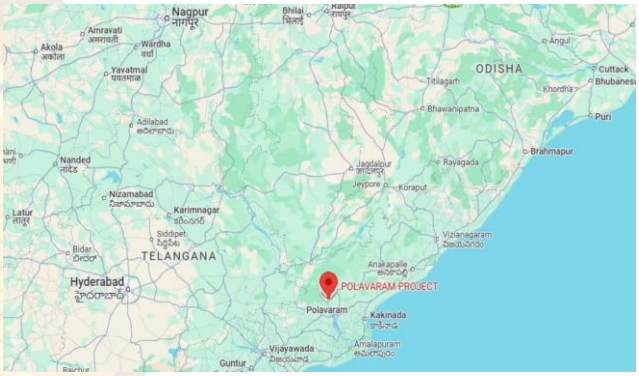

- आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, जिसमें अनिवार्य किया गया कि केंद्र सरकार परियोजना को निष्पादित करे और पर्यावरण, वन, पुनर्वास और पुनर्वास मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे।
- 2016 में, यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% प्रदान करेगा।

बीजेडी ने पोलावरम परियोजना को लेकर क्या चिंताएं जताई हैं?

- बीजेडी का आरोप है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के बाढ़ निर्वहन क्षमता के मूल डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे क्षमता 36 लाख क्यूसेक से बढ़कर 50 लाख क्यूसेक हो गई है।
- बीजेडी का आरोप है यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अपस्ट्रीम राज्यों पर बैकवाटर के प्रभाव पर पर्याप्त विचार किए बिना किया गया था, जो मलकानगिरी की आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिन्हें अपनी जमीन और घर खोने का खतरा है। इसके कारण मलकानगिरी के लगभग 162 गांवों के जलमग्न होने की संभावना है।
- बीजेडी ने जलमग्नता के स्तर के अनुमानों पर विभिन्न अध्ययनों का भी हवाला दिया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश द्वारा 2009 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 50 लाख क्यूसेक बाढ़ के पानी के निर्वहन से ओडिशा में 216 फीट तक जलमग्नता हो सकती है। आईआईटी रुड़की की 2019 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 58 लाख क्यूसेक बाढ़ के पानी के निर्वहन से ओडिशा में 232.28 फीट तक जलमग्नता हो सकती है।

अन्य राज्यों ने भी इस परियोजना के खिलाफ चिंता जताई है?

- ओडिशा के अलावा, छत्तीसगढ़ ने 2011 में और तेलंगाना ने 2019 में इस परियोजना को दी गई मंजूरी और उनके राज्यों में इसके प्रभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
- 11 अप्रैल, 2011 को, सर्वोच्च न्यायालय ने पोलावरम बांध का निरीक्षण करने और यह सत्यापित करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए CWC के पूर्व सदस्य एम गोपालकृष्णन और CWC के अन्य सदस्यों को नामित किया कि बांध का निर्माण GWDT के आदेश के अनुसार है या नहीं। फील्ड विजिट के बाद, जून 2011 में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं।
- दोनों रिपोर्टों में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पोलावरम परियोजना की योजना और सीमित निर्माण गतिविधियाँ स्वीकृत परियोजना और GWDT प्रावधानों के अनुरूप थीं। इसके बाद, अदालत ने तदनुसार सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया और मामला विचाराधीन है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'नकद आरक्षित अनुपात (CRR)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. इसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमाराशि का एक निश्चित प्रतिशत रिज़र्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना होता है।
   2. CRR में समय-समय पर समायोजन रिज़र्व बैंक को बदलती आर्थिक स्थितियों के प्रति गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans: (c)

2. हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय वायुयान विधायक 2024 के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) पुराने विमान अधिनियम, 1954 को बदलना।

   (b) विमानन में सुरक्षा, वनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना।

   (c) नागरिक विमानन प्राधिकरणों के लिए शासन संरचनाओं को शिथिल बनाना।

   (d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

   Ans: (b)

3. RBI की नवीनतम मौद्रिक नीति के तहत प्रमुख नीतिगत दर, रेपो दर (RR) को 'अपरिवर्तित रखने के कारणों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बना रहने की संभावना है।
2. MPC का मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ उच्च विकास के लिए मजबूत आधार सुरक्षित किया जा सकता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

4. हाल ही में चर्चा में रहे 'पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना' की परिकल्पना वर्ष 1980 में किस नदी प्राधिकरण की सिफारिशों के एक भाग के रूप में की गई थी?

(a) गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण

(b) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण

(c) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण

(d) कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण

Ans:(a)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर एक अंतरराज्यीय परियोजना है।
2. आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने इस परियोजना को केवल आंध्र प्रदेश की राज्य परियोजना घोषित किया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(d)